कुछ मुद्दों पर विचार करना ज़रूरी है - भारत में रुग्णता व मृत्यु के अन्य कारणों की तुलना में हिपेटाइटिस-बी की क्या स्थिति है? यदि हिपेटाइटिस-बी टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो इससे इस बीमारी के नियंत्रण या उन्मूलन में कितनी मदद मिलेगी? प्रति जीवन वर्ष बचाने के लिए इसकी लागत कितनी होती है और अन्य टीकों की तुलना में यह कहां बैठता है?

हिपेटाइटिस बी टीके का औचित्य

डॉ. अनन्त फड़के

भारत सरकार अपने विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम में हिपेटाइटिस-बी का टीका शामिल करने की योजना बना रही है। भारतीय शिशु रोग अकादमी (इंडियन एकेडमी ऑफ पिडिएट्रिक्स) कई वर्षों से इसकी सिफारिश करती रही है। अर्थात सरकार के इस कदम को एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संगठन का समर्थन प्राप्त है। मगर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे मात्र चिकित्सकों और नौकरशाहों पर नहीं छोड़ा जा सकता। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा स्वास्थ्य प्रबंधन विशेषज्ञों को भी इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यह बात हिपेटाइटिस-बी टीकाकरण कार्यक्रम पर खास तौर से लागू होती है। इस कार्यक्रम पर मात्र टीके के लिए सालाना 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे (वह भी तब जब मात्र नवजात शिशुओं को ही टीका दिया जाए)। यह आंकड़ा यह मानकर निकाला गया है कि टीके की कीमत वर्तमान कीमत से आधी (50 रुपए) रह जाएगी। यह राशि (125 करोड़ रुपए) टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के केन्द्रीय बजट (2001-2002) के बराबर है। भारत में टी.बी. वयस्क आबादी में सबसे प्रमुख जानलेवा बीमारी है। हिपेटाइटिस-बी के टीके देने की लागत टीकाकरण में दिए जाने वाले अन्य छह टीकों की कुल लागत से भी ज़्यादा है।

इन तथ्यों के मद्देनज़र कुछ मुद्दों पर विचार करना ज़रूरी है - भारत में रुग्णता व मृत्यु के अन्य कारणों की तुलना में हिपेटाइटिस-बी की क्या स्थिति है? यदि हिपेटाइटिस-बी टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो इससे इस बीमारी के नियंत्रण या उन्मूलन में कितनी मदद मिलेगी? इस टीके की लागत क्षमता क्या है यानी प्रति जीवन वर्ष बचाने के लिए इसकी लागत कितनी होती है और अन्य टीकों की तुलना में यह कहां बैठता है? किसी टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करते समय किस स्तर की लागत-क्षमता स्वीकार्य होनी चाहिए?

खास तौर से भारत जैसे विकासशील देश में इन सवालों पर विचार करना अनिवार्य है क्योंकि यहां वित्तीय संसाधनों की हमेशा तंगी रहती है। दूसरी बात यह है कि वैसे भी आधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन को तो यह सोचना ही होगा कि सार्वजनिक धन से संचालित कोई भी हस्तक्षेप कितना लागत-क्षम है। दुर्भाग्यवश, भारतीय शिशु रोग अकादमी या अन्य किसी संस्था ने इन सवालों पर गौर नहीं किया है। इसके बावजूद ये संस्थाएं हिपेटाइटिस-बी टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की वकालत कर रही हैं।

उपरोक्त मुद्दों के गहन विश्लेषण के लिए हमारे यहां